



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
(PUBLISHED BY AUTHORITY)

नं० 30] नई दिल्ली सप्ताह, जुलाई 24, 1993 (श्रावण 2, 1915)
No 30] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 24, 1993 (SRAVANA 2, 1915)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधिवर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . . .	पृष्ठ 611	भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों जिनमें (सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) . . .	पृष्ठ *
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	803	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश . . .	*
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	5	भाग III—खण्ड 1—उप-खण्ड न्यायालयों, निबंध और महाभारत-परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबंध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	701
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	13 49	भाग III—खण्ड 2—वेस्टेज कार्यालय द्वारा जारी की गई वेस्टेजों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	527
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	*	भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . .	*
भाग II—खण्ड 1—क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*	भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	13 289
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के ज्ञापन तथा रिपोर्ट . . .	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तिओं और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	97
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) . . .	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों की कमी से बचा अनुसूची . . .	*
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं . . .	*		

CONTENTS

	PAGE		PAGE
PART I—SECTION 1 —Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	611	PART II —SECTION 3—SUB-SEC. (iii) Authoritative texts in Hindi (other than such texts, Published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2 —Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	803	PART II —SECTION 4 —Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 3 —Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5	PART III —SECTION 1 —Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	701
PART I—SECTION 4 —Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1349	PART III —SECTION 2 —Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	527
PART II—SECTION 1 —Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III —SECTION 3 —Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 1-A —Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III —SECTION 4 —Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	13289
PART II—SECTION 2 —Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART IV —Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	97
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i) —General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART V —Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii) —Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*		

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जून 1993

सं० 27 10 93-सी एन०-2--कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 209 क की उपधारा (1) के खंड (ii) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा कम्पनी कार्य विभाग के श्री जी० सी० गुप्ता उप निदेशक बम्बई को उक्त धारा 209 क के प्रयोजन के लिए प्राधिकृत करती है।

आर एन० वासुधानी
अधर सचिव

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 1993

आदेश

विषय : तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को कच्छ अपतट में के० आई० डब्ल्यू० स्ट्रक्चर के 58 वर्ग कि० मी० क्षेत्र के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की मंजूरी।

सं० ओ०-12012/14/91ओ० एन० जी० डी०-4—पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस नियम, 1959 के नियम 5 के खंड (1) द्वारा प्रवृत्त

शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, तेल भवन, देहरादून को (जिसे इसके पश्चात् आयोग कहा गया है) कच्छ अपतट में के० आई० डब्ल्यू० स्ट्रक्चर के 58 वर्ग कि० मी० क्षेत्र में पेट्रोलियम की संभावना हेतु एक पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस की 21 मार्च 1991 (21-3-1991) से 4 वर्ष के लिए स्वीकृति देती है। इसके विवरण इसके साथ संलग्न अनुसूची "क" में दिए गए हैं।

लाइसेंस की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर है :—

(क) अन्वेषण लाइसेंस पेट्रोलियम के संबंध में होगा।

(ख) यदि अन्वेषण कार्य के दौरान कोई अन्य पदार्थ पाए गए तो आयोग पूर्ण स्मैरे के साथ उसकी सूचना केन्द्रीय सरकार को देगा।

(ग) स्वत्व शुल्क (रायल्टी) निम्नलिखित दरों पर ली जायेगी :—

(i) समस्त अशोधित तेल तथा हैड कम्पेस्ट पर 481 रुपये प्रति मीट्रिक टन या ऐसी दर जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ii) प्राकृतिक गैस के संबंध में ये दरें केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दर के अनुसार होंगी।

स्वत्व शुल्क (रायल्टी) की अदायगी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, नई दिल्ली के वेतन तथा नेवा अधिकारी को की जाएगी।

(ब) आयोग लाइसेंस के अनुसार में प्रत्येक माह के प्रथम 30 दिनों में गल माह से प्राप्त समस्त अशोधित तेल की मात्रा केसिंग हैब कन्वेन्सेट और प्राकृतिक गैस की मात्रा तथा उसका कुल उचित मूल्य बशते वाला एक पूर्ण तथा उचित विवरण केन्द्रीय सरकार को भेजना। यह विवरण संलग्न अनुसूची "ख" में दिए गए प्रपत्र में भर कर देना होगा।

(ङ) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस-नियम 1959 के नियम 11 की अपेक्षाओं के अनुसार आयोग 50,000/- रुपये की धनराशि प्रतिभूति के रूप में जमा करेगा।

(च) आयोग प्रतिवर्ष लाइसेंस के संबंध में एक शुल्क का भुगतान करेगा जिसकी संगणना प्रत्येक वर्ग किलोमीटर या उसके किसी अंश के लिए जिसका लाइसेंस में उल्लेख किया गया होगा निम्नलिखित वर्गों पर को जायेगी :—

- | | |
|------------------------------------|------------|
| (1) लाइसेंस के प्रथम वर्ष के लिए | 8/-रुपये |
| (2) लाइसेंस के द्वितीय वर्ष के लिए | 45/-रुपये |
| (3) लाइसेंस के तृतीय वर्ष के लिए | 200/-रुपये |
| (4) लाइसेंस के चतुर्थ वर्ष के लिए | 400/-रुपये |

द्वितीय वर्ष के लिए 600/-रुपये

(छ) आयोग को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम 1959 के नियम 1959 के नियम 11 के उपनियम (3) की अपेक्षाओं के अनुसार अन्वेषण लाइसेंस में उल्लिखित किसी क्षेत्र के किसी भाग को छोड़कर देने की स्वतन्त्रता सरकार को दो माह की लिखित नोटिस देने के बाव होगी।

(ज) आयोग केन्द्रीय सरकार को मांग किए जाने पर तत्काल तेल तथा प्राकृतिक गैस अन्वेषण के दौरान पाए गए समस्त खनिज पदार्थों के संबंध में भूवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में एक पूर्ण रिपोर्ट गुप्त रूप से भेगा तथा हर 6 महीनों में निश्चित रूप से केन्द्रीय सरकार को समस्त परिवर्तनों, व्यय तथा अन्वेषण कार्यों के परिणामों के बारे में सूचना देगा।

(झ) आयोग समुद्र की "तलछटी" और या उसकी सतह पर आग बुझाने संबंधी निवारक उपायों की व्यवस्था करेगा तथा आग बुझाने हेतु हर समय के लिए उपकरण सामान तथा साधन बनाए रखेगा और तीसरी पार्टी और/या सरकार को उतना मुआवजा देगा जितना कि आग लगने से हुई हानि के बारे में निर्धारित किया जाएगा।

(ञ) इस अन्वेषण लाइसेंस पर तेल क्षेत्र (विनियम और विकास) अधिनियम 1948 (1948 का 53) पर पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस नियम 1959 के उपबंध लागू होंगे।

(ट) पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस के बारे में आयोग केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित एक ऐसे फार्म पर दस्तावेज भेज कर देगा जो अपतटीय क्षेत्रों के लिए व्यवहार्य होगा।

(ड) आयोग खुदाई/ अन्वेषणी आपरेशनों/ सर्वेक्षणों के दौरान एकत्र किए गए बाथीमीट्रिक सतही नमूने, धारा और चुम्बकीय आंकड़े यथा सामान्य रूप से रक्षा मंत्रालय, नौसेना मुख्यालय को प्रस्तुत करेगा।

(ड) आयोग समुद्री विज्ञान आंकड़ों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

(ढ) सम्पूर्ण आंकड़े भारत में संकलित किए जाते हैं।

(ण) यदि विदेशी जलपोत को सर्वेक्षण पर लगाया जाता है तो सर्वेक्षण करने से पूर्व उनका भारतीय नौसेना विशेषज्ञ अधिकारी बल द्वारा नौसेना सुरक्षा निरीक्षण किया जायेगा। भारत में ऐसे जलपोतों के आने के बारे में कम से कम एक माह पूर्व नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि निरीक्षण बल की प्रतिनियुक्ति में सुविधा हो।

(त) इस संबंध में आयोग द्वारा समुद्र विज्ञान संबंधी आंकड़ों की तैयार की गई संपूर्ण प्रति नौसेना मुख्यालय तथा मुख्य हाइड्रोग्राफर को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है।

अनुसूची "क"

के आई डब्ल्यू स्ट्रक्चर (फच्छ अपतट) के लिए 58 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भौगोलिक निदेशांक।

प्लॉट	अक्षांतर	देशांतर
ए	22° 52' 49"	67° 50' 00"
बी	22° 57' 0.2"	67° 56' 40"
सी	22° 55' 04"	67° 58' 01"
डी	22° 50' 51"	67° 51' 20"

अनुसूची "ख"

अशोधित तेल, केंसिंग हेड कन्डेन्सेट तथा प्राकृतिक गैस के उत्पाद तथा उनके मूल्य पहिल मासिक वितरण के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस

क्षेत्रफल

माह तथा वर्ष

(क) अशोधित तेल

कुल प्राप्त मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये गये प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की सं०	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ख) केंसिंग हेड कन्डेन्सेट

प्राप्त किये गये कुल मी० टन की संख्या	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये मी० टन की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये मी० टनों की सं०	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त मी० टन की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

(ग) प्राकृतिक गैस

कुल प्राप्त घन मीटरों की सं०	अपरिहार्य रूप से खोये अथवा प्राकृतिक जलाशय को लौटाये गये घन मीटरों की संख्या	केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य हेतु प्रयोग किये गये घन मीटरों की संख्या	कालम 2 और 3 को घटाकर प्राप्त घन मीटरों की संख्या	टिप्पणी
1	2	3	4	5

एनद्बारा में, श्री..... सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा एवं पुष्टि करता हूँ कि इस विवरण में दी गई सूचना पूर्णरूपेण सत्य और सही है, उसे सही समझते हुए मैं शुद्ध अन्तःकरण से सत्यनिष्ठा से यह घोषणा करता हूँ।

हस्ताक्षर.....

भारत के राष्ट्रपति के आदेश से तथा उनके नाम पर।

एम० मार्टिन,
डेपूट अतिथि

कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 22 जून 1993

संकल्प

सं० 25-1/38-एच० डब्ल्यू०-3--कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार ने भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम 1992 के अन्तर्गत पुनर्वास व्यावसायिकों के प्रशिक्षण को धिनियमित करने के प्रयोजनार्थ एक भारतीय पुनर्वास परिषद का गठन किया है।

2. भारतीय पुनर्वास परिषद का तत्काल प्रभाव से गठन किया गया है और इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. डा० बी० पी० यादव

1/1, सर्वप्रिय बिहार, नई दिल्ली।

संसद सदस्य

2. डा० के० बिजयनाथन, संसद सदस्य (लोक सभा) आंध्र प्रदेश

3. श्री कमल बीधरी, संसद सदस्य (लोक सभा) पंजाब

4. श्री गंठर दयान सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) बिहार

पुनर्वास व्यावसायिक

5. डा० (श्रीमती) उमा तुनी, अध्यक्ष, अमर ज्योति चेरिटेबल-ट्रस्ट, कडक इन्डुमा, दिल्ली।

6. श्री लाल आडवानी, निदेशक (अनुसंधान) नेशनल सोसाइटी फार इन्वेल अफरचुनिटीज फार हैण्डिकैप्ड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, नई दिल्ली।

7. श्री ठाकुर बी० हरी प्रसाद, अध्यक्ष, ठाकुर हरी प्रसाद इंस्टीट्यूट आफ रिसर्च एण्ड रिहाबिलिटेशन फार दी मेंटली हैण्डिकैप्ड चिल्ड्रन, शिणु निकेतन, विवेकानन्द नगर, विलसुख नगर, हैबराबाद।

8. श्री गोकुलनन्द जी०, सचिव, रामकृष्ण मिशन, नरेन्द्रपुर, प० बंगाल

राज्य सरकारें

9. सचिव, समाज कल्याण, दिल्ली।

10. सचिव, समाज कल्याण, महाराष्ट्र।

सरकार के प्रतिनिधि

11. संयुक्त सचिव, (विकलांग कल्याण) कल्याण मंत्रालय

12. श्री ए० के० मुखर्जी स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक, नई दिल्ली।

13. संयुक्त सचिव (कामिक), वित्त मंत्रालय

विकित्सा प्रैक्टीशनर

14. डा० (कर्नल) एस०के० जैन, पुणे (शेष रिक्तियां शीघ्र ही भरी जायेंगी)।

3. अध्यक्ष या कोई सदस्य उसकी नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक या जब तक उसका उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं कर दिया जाता, इसमें जो भी अधिक हो, तक कार्य करेगा।

4. यह परिषद वर्ष में कम से कम एक बार उस समय और उस स्थान पर बैठक करेगी जो परिषद द्वारा नियत किया जाए।

5. परिषद के गैर-सरकारी सदस्य नियमानुसार यात्रा भत्ता वैनिक भत्ते के पात्र होंगे।

6. परिषद के सरकारी सदस्यों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

2. आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों, राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्र, प्रशासनों, मंत्रिभवन सचिवालय, योजना आयोग, प्रधान मंत्री कार्यालय, लोक सभा एवं राज्य सभा सचिवालयों को भेजी जाए।

यू० पी० सिंह,
संयुक्त सचिव

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 3 जून 1993

संकल्प

सं० ई० आर० बी० 1/93/23/19--सरकार ने कोंकण रेल लाइन का निर्माण अनुमोदित कर दिया था और गोवा में इसकी लम्बाई 106 कि० मी० है। इस लाइन पर कार्य पहले ही से चल रहा है।

2. गोवा-मेयम बाली में रेलवे लाइन के प्रस्तावित तटीय संरेखण के विरुद्ध आधार पर अनेक अभ्यावेदन किए गए हैं कि :—

(i) संरेखण से गोवा के घनी आबादी वाले और आवासी क्षेत्र अस्त-व्यस्त हो जायेंगे।

(ii) संरेखण से तथा वनों की भारी कटाई और पहाड़ियों को काटे जाने से पारिस्थितिकी को भारी नुकसान पहुँचेगा जिसमें मांढोडी जुबारी का मुहाना तथा कैरमबोलिम लेक वेस्टलण्ड भी शामिल है।

(iii) खजान लैण्डस गंभीर रूप से प्रभावित होगा जिसके कारण उनके लिए इसकी उपयोगिता कम हो जाएगी।

(iv) प्राचीन गोवा की सांस्कृतिक और पुरातत्त्विक विरासत पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

3. अनेक समितियों और एजेंसियों द्वारा इन मामलों की जांच की गई है परन्तु इस संबंध में परस्पर विरोधी विचार व्यक्त किए जा रहे हैं।

4. इस मामले पर जनता के जोरदार विरोध को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने विनिश्चय किया है कि इस मामले को अन्तिम निर्णय के लिए एक उच्च स्तरीय समिति को सौंप दिया जाए। भारत के उच्चतम न्यायालय से सेवा निवृत्त न्यायाधीश मिस्टर जस्टिस जी० जे० ओमा इस समिति के अध्यक्ष होंगे।

विचारार्थ विषय :

5. समिति के विचारार्थ निम्नलिखित विषय होंगे :—

(i) कोंकण रेलवे लाइन विशेष रूप से निम्नलिखित के संदर्भ में, जहाँ तक यह गोवा में पड़ती है, के लिए उपर्युक्त संरेखण तय करना ;

(क) बन-आछादित क्षेत्र के साथ-साथ मुहाने और खजान लैण्ड दोनों के संबंध में पारिस्थितिकी पर इसका प्रभाव ;

(ख) यह सुनिश्चित करना कि आबादी वाले क्षेत्र में कम से कम व्यवधान पड़े ;

(ग) यह सुनिश्चित करना कि पुरातत्त्विक और सांस्कृतिक धरोहर पर कम से कम प्रभाव पड़े ;

(घ) राज्य को अधिकतम सामाजिक तथा आर्थिक लाभ पहुँचना ;

(ङ.) तकनीकी व्यावहारिकता ;

(च) अभी तक किए जा चुके कार्य को ध्यान में रखते हुए अधिक-तम किफायती लागत और समय-बद्ध कार्यक्रम ;

(छ) स्थल का निरीक्षण करना ;

(ज) पीड़ित व्यक्तियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करना और उपर्युक्त के संदर्भ में उनके विचार जानना।

(ii) इस संबंध में किसी निर्णय पर पहुँचने के लिए समिति इस मुद्दे पर किए गए पिछले अध्ययनों पर भी विचार करेगी।

(iii) समिति सरकार को उपयुक्त कार्रवाई करने की सिफारिश करेगी।

6. समिति अपने नियमों और प्रक्रियाओं को तय करेगी और उसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को सहयोगित करने का प्राधिकार होगा जिसे वह अपने काम में सहयोग देने के लिए उपयुक्त समझे।

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

New Delhi-110 001, the 30th June 1993

No. 27/10/93-CL.II.—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (1) of Section 209-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Central Government hereby authorise Shri G. C. Gupta, Deputy Director Inspection, Bombay in the Department of Company Affairs for the purpose of the said section 209-A.

R. N. VASWANI, Under Secy.

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS
New Delhi, the 24th June 1993
ORDER

Subject:—Grant of Petroleum Exploration Licence to Oil and Natural Gas Commission for KIW structure area measuring 58 sq. kms., (Kutch offshore)

No. O-12012/14/91-ONG.D.IV.—In exercise of the powers conferred by clause (i) of Rules 5 of the Petroleum and Natural Gas Rules, 1959, the Central Government hereby grants to the Oil and Natural Gas Commission, Tel Bhavan, Dehradun (herein after referred to as Commission), a Petroleum Exploration Licence to prospect for petroleum for four years from 21st March, 1991 (21-3-1991) for KIW structure (Kutch Offshore) area measuring 58 sq. kms., the particulars of which are given in Schedule 'A' annexed hereto.

The grant of Licence is subject to the terms and conditions mentioned below :—

- (a) The Exploration Licence should be in respect of Petroleum.
- (b) If any minerals are found during the exploration work, the Commission should bring that to the notice of the Central Government with full particulars thereof.
- (c) Royalty at the rate mentioned below shall be charged :—
 - (i) Rs. 481/- per metric tonne or such rates as may be fixed by the Central Government from time to time on all crude oil and casing-head condensate.
 - (ii) In case of natural gas, at such rates as may be fixed by the Central Government from time to time. The royalty shall be paid to the Pay and Accounts Officer, Ministry of Petroleum and Natural Gas, New Delhi.
- (d) The Commission shall within the first 30 days of every month, furnish to the Central Government, a full proper return showing the quantity and gross value of all crude oil, casing-head condensate and natural gas obtained during the preceding month in pursuance of the licence. The return shall be in the form given in Schedule 'B' annexed hereto.
- (e) The Commission shall deposit a sum of Rs. 50,000/- as security as required by rule 11 of the P&NG Rules, 1959.
- (f) The Commission shall pay every year in advance a fee in respect of the licence calculated at the following rates for each square kilometre or part thereof covered by the licence :—
 - (i) Rs. 8/- for the first year of the licence;
 - (ii) Rs. 40/- for the second year of the licence;

7 समिति एक महीने के अन्दर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक सूचना के लिए मंत्रालय को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

सतीशकुमार
सचिव, रेलवे बोर्ड

- (iii) Rs. 200/- for the third year of the licence;
- (iv) Rs. 400/- for the fourth year of the licence;
- (v) Rs. 600/- for the first and second year of renewal.
- (g) The Commission shall be at liberty to determine the relinquishing of any part of the area covered by the exploration licence by giving not less than two month's notice in writing to the Central Government as required by sub-rule (3) of the rule 11 of the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (h) The Commission shall immediately on demand submit to Central Government confidentially a full report of the Geological data of all the minerals found during the exploration of oil and natural gas and shall submit without fail every six months the results of all operations, boring and exploration to the Central Government.
- (i) The Commission shall take preventive measures against the hazards of fire under sea bed and/or on the surface and shall keep such equipment, supplies and means to extinguish the fire at all times and shall pay such compensation to third party and/or Government as may be determined in case of damage due to the fire.
- (j) This exploration licence shall be subject to the provisions of the Oil Fields (Regulation & Development) Act, 1948 (53 of 1948) & the Petroleum & Natural Gas Rules, 1959.
- (k) The Commission shall execute a deed of the Petroleum Exploration Licence in the form applicable to Offshore areas as approved by the Central Government.
- (l) The Commission should render, Bathymetric bottom samples, Current and magnetic data collected during the drilling/exploration operations/survey, to Ministry of Defence, Naval Headquarters in the usual manner.
- (m) The Commission should ensure security of oceanographic data.
- (n) The entire data is precessed in India.
- (o) Foreign vessels if deployed for survey, are to undergo naval security inspection by a team of Indian Navy Specialists/Officers prior to commencement of survey. A minimum of one month notice about the arrival of such vessel in India is to be given to facilitate deputation of the Inspection team.
- (p) A complete of oceanographic data collected by the Commission in this area is made available free of cost to the Ministry of Defence/Chief Hydrographer.

SCHEDULE 'A'

Geographical coordinates of KIW structure (Kutch offshore) area measuring 58 sq. kms.

Point	Latitude			Longitude		
A	22°	52'	49"	67°	50'	00"
B	22°	57'	02"	67°	56'	40"
C	22°	55'	04"	67°	58'	01"
D	22°	50'	51"	67°	51'	20"

SCHEDULE 'B'

Monthly return of crude oil, casing-head condensate and natural gas
produced and value thereof.

Petroleum Exploration Licence for
Area

Month and Year

A—Crude Oil

Total No. of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purpose of petroleum exploration operation approved by the Central Govern- ment	No. of Metric tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3		

B—Casing-head condensate

Total Number of Metric Tonnes obtained	No. of Metric Tonnes unavoidably lost or returned to natural reservoir	No. of Metric Tonnes used for purposes of petroleum exploration approved by Central Government	No. of Metric Tonnes obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

C—Natural Gas

Total Number of cubic Metres obtained	Number of cubic metres unavoidably lost or returned to natural reservoir	Number of cubic metres used for pur- poses of petroleum exploration approved by the Central Govern- ment	Number of cubic metres obtained less columns 2 and 3	Remarks
1	2	3	4	5

I, Shri _____ do hereby solemnly and sincerely declare, and affirm that the information in this return is true and correct in every particular and make this declaration conscientiously believing the same to be true.

By order and in the name of the President of India.

(Signature)

M. MARTIN,
Deputy Officer

MINISTRY OF WELFARE

New Delhi-110 001, the 22nd June 1993

RESOLUTION

No. 25-1/88-H.W-III.—The Ministry of Welfare, Government of India have for the purpose of regulating the training of rehabilitation professionals set up Rehabilitation Council of India under the Rehabilitation Council of India Act, 1992.

2. With immediate effect the Rehabilitation Council of India has been constituted and shall consist of the following members :—

Chairman

1. Dr. B. P. Yadav.

11, Serva Priya Vihar, New Delhi.

Members of Parliament

2. Dr. K. Viswanadham, M.P. (Lok Sabha), Andhra Pradesh.

3. Shri Kamal Chaudhry, M.P. (Lok Sabha), Punjab.

4. Shri Shankar Dayal Singh, M.P. (Rajya Sabha), Bihar.

Rehabilitation Professionals

5. Dr. (Mrs.) Uma Tuli, President, Amar Jyoti Charitable Trust, Karkarduma, Delhi.

6. Shri Lal Advani, Director (Research), National Society for Equal Opportunities for Handicapped, Lal Bahadur Shastri Marg, New Delhi.

7. Shri Thakur V. Hari Prasad, Chairman, Thakur Hari Prasad Institute of Research and Rehabilitation for the Mentally Handicapped Children, 'Sishu Niketan', Vivekananda Nagar, Dilsukhnagar, Hyderabad.

8. Shri Gokulanandaji, Secretary, Ramakrishan Mission, Narinderpur West Bengal.

State Governments

9. Secretary, Social Welfare, Delhi.

10. Secretary, Social Welfare, Maharashtra.

Government's Representatives

11. Joint Secretary (Handicapped Welfare), Ministry of Welfare.

12. Shri A. K. Mukherjee, Director General of Health Services, New Delhi.

13. Joint Secretary (Perks), Ministry of Finance.

Medical Practitioner

14. Dr. (Col.) S. K. Jain, Pune.

The remaining vacancies will be filled up in due course.

3. The Chairman or a member shall hold office for a term of two years from the date of his appointment or until his successor shall have been duly appointed, whichever is longer.

4. The Council shall meet at least once in each year and such time and place as may be appointed by the Council.

5. The non-official members of the Council shall be eligible for TA/DA as provided under rules.

6. No remuneration will be paid for the official members of the Council.

ORDER

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

2. Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries/Departments of Government of India, State Governments, Administrators of the UTs, Cabinet Sectt., Planning Commission, Prime Minister's Office, Lok Sabha and Rajya Sabha Sectt.

U. P. SINGH, Jt. Secy.

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 3rd June 1993

RESOLUTION

No. ERB-I/93/23/19.—The Government had approved the construction of the Konkan Railway line which runs for 106 Kms. through Goa. Work on this line is already in progress.

2. A number of representations have been made against the proposed coastal alignment of the railway line in Goa (Mayem Bali) on the grounds that :

(i) The alignment disrupts the densely populated and settled areas of Goa.

(ii) There would be serious damage to the eco-system including to the Mandovi Zuvari estuary, the Carambolim lake wasteland, and through heavy deforestation and hill-cutting.

(iii) The Khazan lands would be seriously affected causing degradation to them.

(iv) The cultural and archaeological heritage of old Goa would be seriously affected.

3. These issues have been examined by a number of committees and agencies, but conflicting views continue to exist.

4. In view of the strong representations by the public on this issue, the Government of India have decided to refer the matter to a High level Committee for a final decision. The Committee will be headed by Mr. Justice G. J. Oza, Retd. Judge, Supreme Court of India.

Terms of Reference :

5. The Committee shall have the following terms of reference :

(i) To decide upon a suitable alignment for the Konkan Railway, in so far as it lies in Goa (Mayem-Bali) with particular reference to the following :—

(a) The effect on the eco-system, both with respect to the estuarine and khazan land areas as well as forest cover;

(b) the need to minimise the disruption of human settlements;

(c) the need to minimise the effect on archaeological and cultural heritage;

(d) to provide the maximum social and economic benefit to the State;

(e) technical feasibility;

(f) the most economical cost and time frame, taking into account work already done so far.

(g) to visit the site;

(h) to meet and listen to representatives of aggrieved persons and their view point in the above context.

(ii) In arriving at its decision, the Committee shall also consider the previous studies on this issue.

(iii) The Committee shall recommend a suitable course of action to Government.

6. The Committee shall decide its own rules and procedures and shall have the authority to co-opt any person it considers appropriate to assist in its work.

7. The Committee shall submit its report within one month.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

MASIHUZZAMAN Secy.
Railway Board.